



ग्रामीण भारत: प्रगति और समस्याएँ

यह एडिटरियल 04/08/2023 को 'हृद्दि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित ["Rural poverty declines, but lifestyle issues emerge"](#) लेख पर आधारित है। इसमें ग्रामीण विकास और ग्रामीण भारत की प्रगति में नीति आयोग की भूमिका के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिम्स के लिये:

[बहुआयामी गरीबी सूचकांक](#), नीति आयोग, [राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन \(NRLM\)](#), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MNREGA), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना (सौभाग्य), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

मेन्स के लिये:

ग्रामीण विकास से संबंधित चुनौतियाँ।

भारत वरिधाभासों का देश है, जहाँ तीव्र आर्थिक विकास के साथ ही सतत गरीबी और सामाजिक समस्याओं का सह-अस्तित्व पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ देश की लगभग दो-तहई आबादी नविस करती है, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुज़र रहे हैं।

जैसे-जैसे भारत का ग्रामीण परदृश्य एक परिवर्तनकारी यात्रा से गुज़र रहा है, जहाँ बहुआयामी गरीबी (multidimensional poverty) में आशाजनक गिरावट आ रही है, परिवर्तनों की एक जटिल तस्वीर भी सामने उभर रही है। नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी अद्यतन [राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक \(National Multidimensional Poverty Index- MPI\)](#), प्रगतिके एक उत्साहजनक आख्यान को उजागर करता है, जहाँ वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीबी दरों (poverty rates) में पर्याप्त कमी नज़र आई है।

नीति आयोग का राष्ट्रीय MPI:

- परिचय: राष्ट्रीय MPI गरीबी की एक माप है जो तीन समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों— स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में किसी देश की प्रगति को दर्शाता है।
 - यह 10 संकेतकों पर विचार करता है जसमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, रसोई ईंधन, स्वच्छता आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय MPI के घटक: राष्ट्रीय MPI को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है-
 - गरीबी की स्थिति (incidence of poverty)—यानी गरीब लोगों का प्रतिशत और गरीबी की तीव्रता (intensity of poverty)—यानी गरीबों का औसत अभाव स्कोर (average deprivation score)।
- राष्ट्रीय MPI के नषिकर्ष: नीति आयोग की प्रगतिसमीक्षा 2023 के अनुसार, भारत ने वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
 - इस अवधि में गरीबी की स्थिति 24.85% से घटकर 14.96% हो गई, जबकि गरीबी की तीव्रता 47.14% से घटकर 44.39% हो गई।
 - ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई जहाँ यह 32.59% से घटकर 19.28% हो गई।
 - ग्रामीण गरीबी में सुधार का श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य हतिधारकों द्वारा की गई विभिन्न लक्षित विकास पहलों को दिया जा सकता है।

ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के संकेत:

- उन्नत आवास अवसंरचना:
 - पक्के या अर्द्ध पक्के घरों तक पहुँच में वृद्धि बेहतर संरचनात्मक पहुँच और बेहतर जीवन स्थितिका प्रतीक है।
 - टिकाऊ आवास प्राकृतिक घटकों के वरिद्ध प्रत्यास्थता को बढ़ावा देता है, जससे ग्रामीण नविसियों के लिये सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ने ग्रामीण आवास की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

- **बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ:**
 - शौचालयों की वृहत उपलब्धता स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने और खुले में शौच एवं संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने की स्थिति को प्रकट करती है।
 - बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ सामुदायिक कल्याण और स्वच्छ वातावरण में योगदान देती हैं।
 - उदाहरण के लिये, स्वच्छ भारत मशिन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत 1 लाख से अधिक गाँवों ने स्वयं को ODF प्लस (खुले में शौच मुक्त- प्लस) घोषित किया है।
- **वदियुत तक वसितारति पहुँच:**
 - बजिली तक पहुँच का वसितार ग्रामीण समुदायों को बेहतर कनेक्टविटी, प्रकाश व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों के अवसरों के साथ सशक्त बनाता है।
 - बजिली बेहतर शैक्षिक प्रतफिल, उत्पादकता में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को सक्षम बनाती है।
 - उदाहरण के लिये:
 - ग्रामीण वदियुतीकरण के वसितार के लिये [प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना \(सौभाग्य\)](#) शुरू की गई है।
- **स्वच्छ रसोई ईंधन को अपनाना:**
 - स्वच्छ रसोई गैस के बढ़ते उपयोग से घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी आती है, जिससे श्वसन स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
 - स्वच्छ रसोई ईंधन संवहनीय पर्यावरणीय अभ्यासों का समर्थन करता है; इस प्रकार, एक स्वस्थ पारस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है।
 - [प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना \(PMUJ\):](#)
 - उज्ज्वला 1.0 के तहत मार्च 2020 तक BPL परिवारों की 50 मिलियन महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।
 - उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान किये जाने थे।
- **शैक्षिक और सामाजिक सशक्तीकरण:**
 - शिक्षा में बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी प्रगतशील सामाजिक मूल्यों को दर्शाती है और लैंगिक समानता एवं समावेशी विकास में योगदान देती है।
 - कनेक्टविटी के माध्यम से ज्ञान का प्रसार शैक्षिक विकास में सहायता करता है और सूचना-संपन्न नरिणयन को बढ़ावा देता है।
 - उदाहरण के लिये: [सांसद आदर्श ग्राम योजना](#) का उद्देश्य ग्रामीणों को विकल्प चुनने के लिये सशक्त बनाना और उन्हें उन विकल्पों का उपयोग करने के अवसर प्रदान करना है।
- **आय स्रोतों का वविधीकरण:**
 - गैर-कृषि रोजगार के बढ़ते अवसरों से आय के स्रोतों में वविधिता आती है, जिससे केवल कृषि पर नरिभरता कम हो जाती है।
 - आय वविधीकरण कृषि से जुड़ी अनश्चितताओं के वरिद्ध ववितीय स्थिरता और परत्यास्थता को बढ़ाता है।
 - उदाहरण के लिये:
 - [मनरेगा \(MGNREGA\)](#): योजना का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को **प्रत्येक ववितीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है।**
 - [राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन \(NRLM\)](#) का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिये कुशल और प्रभावशील संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि और ववितीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।
- **ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य सरकारी पहलें:**
 - [सार्वजनिक वितरण प्रणाली \(PDS\)](#)
 - [मशिन अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना](#)
 - [प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना](#)

ग्रामीण भारत के विकास से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

- **गरीबी और असमानता:**
 - व्यापक गरीबी की स्थिति बनी हुई है, जो नमिन आय, बुनियादी सेवाओं तक सीमति पहुँच और संसाधनों के असमान वितरण जैसी वशिषताएँ रखती है।
 - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तथा ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर आय असमानता की स्थिति समतामूलक विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
- **कृषिसंकट:**
 - प्राथमिक आजीविका स्रोत के रूप में कृषि पर नरिभरता ग्रामीण समुदायों को अपरत्याशति मौसम पैटर्न, बाजार के उतार-चढ़ाव और फसल वफिलताओं से उत्पन्न जोखिमों के प्रता संवेदनशील बनाती है।
 - वखिंडति भूमि जोत, अपर्याप्त सचिआई सुविधा और पुरानी पड़ चुकी कृषि पद्धतियाँ उत्पादकता एवं आय सृजन में बाधा उत्पन्न करती हैं।
- **बेरोजगारी और अल्प-रोजगार:**
 - अपर्याप्त गैर-कृषि रोजगार अवसरों के कारण कृषि क्षेत्र में [मौसमी बेरोजगारी](#) और [अल्प-रोजगार](#) की स्थिति उत्पन्न होती है।
 - कुशल विकास और बाजार-उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी वभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यबल की भागीदारी को सीमति करती है।
- **अवसंरचनात्मक अंतराल:**
 - सड़क, बजिली और दूरसंचार सहति अपर्याप्त ग्रामीण कनेक्टविटी बाजारों, सेवाओं एवं सूचना तक पहुँच को सीमति करती है।

- कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता सुविधाएँ और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएँ अपर्याप्त हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि:**
 - ग्रामीण क्षेत्र सूखा, बाढ़, ग्रीष्म लहर और चरम मौसमी घटनाओं जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की चपेट में आते हैं।
 - ये जल, मृदा और वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं तथा ग्रामीण समुदायों, विशेषकर किसानों एवं चरवाहों की आजीविका पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।

उदाहरण के लिये, वर्ष 1990 और 2016 के बीच खेत में वचिरण करने वाले पक्षियों (farmland birds) की आबादी में एक तिहाई की गिरावट आई है।

प्रवासन और शहरीकरण:

- ग्रामीण क्षेत्र बाह्य प्रवासन की उच्च दर का सामना कर रहे हैं जहाँ बेहतर अवसरों और सेवाओं की तलाश में विशेष रूप से और शक्ति लोगो का शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हो रहा है।
- इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमबल की कमी, भूमिखिंडन, सामाजिक अलगाव और सांस्कृतिक पहचान की हानि की स्थिति बिन सकती है।
- दूसरी ओर शहरीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है, जैसे बेहतर कनेक्टिविटी, बाज़ार पहुँच, धन प्रेषण और नवाचार।
- **नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य:**
 - ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और वयस्कों के बीच तंबाकू, गुटखा, शराब और सोशल मीडिया की लत बढ़ रही है।
 - इनका ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य, उत्पादकता, सामाजिक संबंधों और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
 - इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता का अभाव होता है, जिससे तनाव, अवसाद, आत्महत्या और हिसा की स्थिति बिन सकती है।
- **अपशष्टि प्रबंधन और स्वच्छता:**
 - ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः उचित अपशष्टि प्रबंधन प्रणालियों एवं सुविधाओं- जैसे स्रोत पर पृथक्करण और जैविक/अजैविक अपशष्टि के लिये क्रमशः कम्पोस्टिंग/बायोगैस संयंत्र/रीसाइकलिंग इकाइयों आदि का अभाव पाया जाता है।
 - इससे पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, सौंदर्य संबंधी गिरावट और संसाधनों की हानि की स्थिति बिन सकती है।
 - ग्रामीण क्षेत्रों को अभी भी स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छता अभ्यासों तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये संभावित समाधान:

- **स्थानीयकृत रोज़गार के अवसर:**
 - कौशल विकास और उद्यमशीलता के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल को सहारा मिल सकता है।
 - कौशल विकास कार्यक्रमों, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने, ग्रामीण अवसंरचना के विकास आदिके माध्यम से गाँवों के नजिक रोज़गार के अधिक अवसर सृजित किये जाने चाहिये।
 - इससे प्रवासन की वविशता कम हो सकती है, ग्रामीण लोगों की आय एवं आजीविका सुरक्षा बढ़ सकती है और उनकी आत्मनिर्भरता एवं गरमा की संवृद्धि हो सकती है।
- **व्यसन और मादक द्रव्यों के सेवन पर अंकुश:**
 - तंबाकू, गुटखा और शराब के उपभोग को कम करने के लिये कठोर वनियमन और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है।
 - समग्र सामुदायिक हस्तक्षेप स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दे सकते हैं और मादक द्रव्यों पर निर्भरता पर अंकुश लगा सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी के उपयोग को संतुलित करना:**
 - अत्यधिक इंटरनेट उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से स्वस्थ डिजिटल आदतों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
 - सामुदायिक पहले पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दे सकती है और सामाजिक बंधनों को सुदृढ़ कर सकती है।
- **व्यापक अपशष्टि प्रबंधन:**
 - **स्वच्छ भारत मिशन 2.0** को स्रोत पर पृथक्करण, जैविक/अजैविक अपशष्टि के लिये क्रमशः कम्पोस्टिंग/बायोगैस संयंत्र/रीसाइकलिंग इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अपशष्टि प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
 - इससे ग्रामीण क्षेत्रों की पर्यावरणीय गुणवत्ता, स्वास्थ्य स्वच्छता और संसाधन दक्षता में सुधार हो सकता है तथा ग्रामीण लोगों के लिये आय एवं रोज़गार के अवसर भी सृजित हो सकते हैं।

ग्रामीण मुद्दों को हल करने में नीतिआयोग की भूमिका:

- **नीतिआयोग:**
 - ऐसी नीतियों का निर्माण कर सकता है जो विशेष रूप से व्यसन, डिजिटल निर्भरता और अपशष्टि प्रबंधन जैसी ग्रामीण चुनौतियों को लक्ष्य करें।
 - व्यापक समाधानों के लिये सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, नजी क्षेत्र और समुदायों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकता है।
 - इन चुनौतियों के मूल कारणों और उनकी क्षेत्रीय विविधताओं को समझने के लिये अध्ययन आयोजित करा सकता है और इस प्रकार,

प्रभावी समाधान का सृजन करने में सहायता कर सकता है।

- सुदृढ़ नगिरानी प्रणालियों के कार्यान्वयन से वभिन्न पहलों की प्रगतिका आकलन कथिा जा सकता है और इष्टतम प्रभाव के लयि रणनीतयिों को अनुकूलतम बनाया जा सकता है।
- नशे की लत, प्रौद्योगिकी पर नरिभरता, अपशषिट प्रबंधन और अन्य वषियों को हल करने वाली अभनव परयोजनाओं का समर्थन एवं वतितपोषण कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न: नीतआयोग की नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) रपिरट के आलोक में ग्रामीण भारत के वकिस की उपलब्धयिों और चुनौतयिों की चरचा कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वरष प्रश्न

??????????:

प्रश्न. UNDP के समर्थन से 'ऑक्सफोर्ड नरिधनता एवं मानव वकिस नेतृत्व' द्वारा वकिसति 'बहुआयामी नरिधनता सूचकांक' में नमिनलखिति में से कौन-सा/से सम्मलिति है/हैं? (2012)

1. पारवारिक स्तर पर शकषिा, स्वास्थ्य, संपत्त और सेवाओं से वंचन
2. राष्ट्रीय स्तर पर कर्य शकती समता
3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की वकिस दर

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

??????????:

प्रश्न. उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव वकिस के नमिनतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीकषण कीजयि, जो संतुलति और समावेशी वकिस में बाधक हैं। (2019)